he rivalry between the State Department and the Central Department has created, a lot of inconvenience not only in Goa but in other cities also I feel that the Ministry should see that the co-ordination committees of the State Electricity Department and the P.W.D. and th Central Telecom Department function effectively. Madam, the main fraud in Goa, as it is rumoured, is that we have a PCO system, the public call office system, and these public call offices are cornered by the staff themselves in the name of trTeir friends or through benami. And it is said that all the telecom network in Goa has been put to a standstill, and only these PCOs are functioning. The idea is that the people should go to the PCOs and make the calls. These calls are not metered. As a result, the Department is cheated of lakhs and lakhs of rupees in revenue. I requested the hon. Minister in the last session that he should conduct a CBI inquiry into it. I still insist that this inquiry should be conducted to see why the public telephone system is bad and only the PCOs are functioning in the State.

Madam, in the month of January, to be precise, on the 7th of January, 1992, the hon. Minister appointed two telephone advisory committee for Goa and Panjim. And I am one of the members on both the committees. But till today, these committees are not functioning. TJie telecom officers are involved in a fraud, and the telephone connections are sold out to people out of turn. In fact, there are Departmental staff who are going from shop to shop as salesmen enquiring with the people whether they would like to buy a telephone. These telephones are sold for Rs. 2»t,W0 to Rs. 25,000 per connection. Therefore, I would request the hon. Minister to see that the TACs are made functional immediately. They should issue fresh notifications and reactivate these Commttees. Madam, even the hon. Chief Minister of Goa had to make a public statement that this gentleman, the DM(T) should be suspended or transferred immediately because the whole Government has come to a standstill and even the Raj Bhawan telephones were not functioning. Therefore, to set things in order, I would request that the Central Government should take immediate interest in the matter. Goa is far away. I don't think that it is a problem with Goa alone There is no control, there are no checks. The Ministry should take interest and see that a CBI inquiry is instituted and all these allegations are investigated, and the telephone system is put in order with immediate effect. Thank you, Madam.

डा० बलदेव प्रकाश (उत्तर प्रदेश) : मैडम, मेरा एक स्पेशल मैंशन था 8 तारीख के लिए नंबर फाइव पर। पर उस दिन नहीं हो सका था, टाइम खत्म हो गया था।

उपसभापति : मुझे लगता है कुछ गलती हो गई, ओवरसाइट हो गया तो आपका नहीं लिख पाए। आज बोल दीजिए। आपको परमिट किया था तो आज बोल दीजिए।

Kiljing of a BJP leader in Faridkot district of Punjab by the police

डा० बलदेव प्रकाश (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदया, मेरा स्पैशल मैंशन जो है वह पंजाब में फरीदकोट जिले के अंदर कोटकपूरा टाउन में हुई घटना के बारे में है। वहां एक विधायक और एक मंत्री के अंगरक्षकों द्वारा शांति से पुलिस स्टेशन पर डैमोन्स्ट्रेशन कर रहे लोगों पर गोली चलाई जिसमें हमारे वहां के भारतीय जनता पार्टी के उप-प्रधान की हत्या हो गई और 8 व्यक्ति बहुत ही गंभीरतापूर्वक घायल हो गए।

उपसभापति महोदया, यह बहुत गंभीर विषय है। पंजाब के अंदर हजारों व्यक्तियों को अंगरक्षक मिल हुए हैं और

[डा० बलदेव प्रकाश]

एक-एक व्यक्ति के साथ आठ-आठ दस-दस अंगरक्षक चलते हैं और अंगरक्षक का केवल एक ही कर्तव्य है कि वह उस नेता को, उस विधायक को या उस मंत्री को आतंकवादियों से, टैररिस्टों से बचायें न कि वहां जो लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं या जो लोग मंत्री का मिलने जाते हैं उनके ऊपर गोलीबारी करें। वहां पर ऐसा हुआ है। इससे एक ऐसी गलत परंपरा कायम हो गई है। अगर इस प्रवृति को और बढ़ाया गया तो जो हजारों अंगरक्षक हैं, जिनको हथियार मिले हुए हैं और वे सभी नेताओं के साथ घूमते फिरते हैं, अगर इस तरह से उनको गोली चलाने देंगे तो फिर पता नहीं यह कहां तक बात बढ़ेगी और किस सीमा तक जाएगी और पंजाब को एक दूसरे आतंकवाद का सामना करना पड़ेगा।

मैं समझता हूं कि पंजाब सरकार को फौरन इस पर ऐक्शन लेना चाहिए। अंगरक्षक का यह काम नहीं है कि वह आम जनता पर गोली चला दे। वह तभी संभव हो सका जब कि उनको थोड़ा-बहुत प्रोत्साहन मिला था विधायक या मंत्री का और उसके कारण गोली चलाई गई। वहां पर बहुत रिजेंटमैंट है। बंद हुआ। वहां शहर बंद रहा और लोगों की यह मांग है कि जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए मैं चाहता हूं कि केन्द्र की सरकार और गृह मंत्री इसका नोटिस लें और इसकी जांच करवाकर यहां पर सदन में एक स्टेटमेंट दें और जिस अंगरक्षक ने गोली चलाई है या जिन अंगरक्षकों ने गोली चलाई है, उन पर मुकदमा दायर हो और उनको सज़ा मिले, यह मेरा निवेदन है।

उपसभापति: Now, we have two minutes. आपके साथ तो कोई मेडन भी बोलने वाले हैं। तो दो मिनट में तो मेडन का चक्कर हो नहीं सकता। लंबा होता है। ईश दत्त यादव जी, अगर आप एकदम जल्दी से बोल दें गंगा के बारे में तो फिर हम हाऊस को लंच के लिए ऐडजार्न करें।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): 4 मिनट लगेगा, मेडम, ज्यादा नहीं।

उपसभापति: 2 मिनट कर दीजिए। गंगा बहुत लंबी है तो इसका मतलब यह थोड़ी कि इतना लंबा बोलना है।

Failure of Ganga Action Plan

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): मैडम, बहुत पहले, कुछ साल पहले एक फिल्म बनी थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): उन पापियों के पाप धोते-धोते.....

उपसभापति: अब चलिए, पाप किसके धोये वह तो गंगा जब बोलेगी तब पता लगेगा, अभी तो ईश दत्त जी को बोलने दीजिए (**व्यवधान**)

श्री ईश दत्त यादव: मैं समझता हूं मैडम, इसी से प्रेरणा ले करके भारत सरकार ने केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण और गंगा कार्य योजना की स्थापना की थी गंगाजल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। मैडम, इसकी जो कमेटी बनाई गई, समिति बनाई गई, प्रधान मंत्री जी इसके अध्यक्ष हैं, आज भी हैं, और उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और इन तीनों प्रदेश के एक एक संसद सदस्य इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं। इस प्राधिकरण ने कुल 261 योजनाओं को लागू किया जिसमें यह कहा गया कि मल-जल उपचार किया जाएगा, गंदे पानी का मार्ग परिवर्तन किया जाएगा, विद्युत शवदाह गृहों की स्थापना की जाएगी, औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित जल की रोकथाम होगी, और गंगा में कछुवों को छोड़ा जाएगा, इनका प्रजनन बढ़ाया जाएगा ताकि पानी की सफाई होती रहे। लेकिन 1985 से लेकर आज तक मैं सरकार की रिपोर्ट के आधार पर कहना चाहता हूं कि यह सारा पैसा जो केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण का था उसके सारे अधिकारियों ने सारा पैसा हड़प